संख्या 114 [illegible]/18(1)/2006

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

राजस्व विभाग देहरादून : दिनांक : 02 [illegible], 2007

विषय: चेस्टनेट हाईटस् प्रा0लि0 को ईको टूरिज्म व्यवसाय हेतु तहसील धारी के ग्राम जिलिंग में कुल 15.314 है0 भूमि क्रय करने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–696/12–जेड0ए0सी0/2006 दिनांक 02 दिसम्बर, 2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चेस्टनेट हाईटस् प्रा0लि0 को ईको टूरिज्म व्यवसाय हेतु उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा–154(2) एवं उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15–1–2004 की धारा– 154(4)(3)(क)(II) के अन्तर्गत तहसील धारी के ग्राम जिलिंग में कुल 15.314 है0 भूमि क्रय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं :–

1– क्रेता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2– क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा–129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3– क्रेता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगे।

........(2)

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6– आवेदक स्थापित किये जाने वाले उद्योग में उत्तरांचल के निवासियों को 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन उपलब्ध करायेगा।

7– इकाई द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग ईको टूरिज्म व्यवसाय हेतु ही किया जायेगा।

8– परियोजना की स्थापना से पूर्व पर्यावरण प्रदूषण के सम्बन्ध में नियत प्राधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जानी होगी।

9– परियोजना हेतु सार्वजनिक अवस्थापना सुविधाओं का उपभोग सम्बन्धित विभागों की अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा।

10– उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

2– तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन०एस०नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
2– आयुक्त, कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल।
3– सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तरांचल शासन।
4– श्री राजीव लुंगड, डायरेक्टर, चेस्टनेट हाईटस् प्रा०लि०, निवासी– 36 ब्लॉक–III, प्राग–चार्मवुड, फरीदाबाद, हरियाणा।
5– निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तरांचल सचिवालय परिसर, देहरादून।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुशील सिंह)
अनु सचिव।